भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या * 272

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

पोषण ट्रैकर कार्यक्रम

***272. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:**
डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में बच्चों के लिए पोषण अभियान लागू कर रही है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पोषण ट्रैकर कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार बच्चों के विकास और पोषण की स्थिति की प्रभावी निगरानी किस प्रकार होती है;

(ग) देश में उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों में इसे किस तरह अपनाया गया है;

(घ) उक्त कार्यक्रम के तहत विकास की नियमित निगरानी के माध्यम से हर माह कितने बच्चों की माप की जाती है तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करने के संबंध में इस माप के क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं; और

(ङ) उपर्युक्त क्षेत्रों जैसे ग्रामीण और अल्पविकसित क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र में बाल स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए पोषण ट्रैकर कार्यक्रम की सफलता का लाभ किस प्रकार उठाया जाएगा?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

****

"पोषण ट्रैकर कार्यक्रम" के संबंध में श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी और डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 272 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पोषण अभियान मार्च 2018 में शुरू किया गया था। 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

यह सार्वभौमिक, स्वयं-चयनित (कोई प्रवेश बाधा नहीं) योजना आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकन कराने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

इस मिशन के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक

व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन एक प्रमुख कार्यकलाप है। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

(ख) से (ङ): आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणाली का लाभ उठाया गया है। 01 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण आईटी गवर्नेंस टूल के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। यह आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, और परिभाषित संकेतकों पर लाभार्थियों की पहचान करता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को महीने में एक बार सभी बच्चों (0-6 वर्ष) का कद और वजन मापने का अधिदेश दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दर्ज किए गए कद और वजन के आंकड़ों के आधार पर, डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन, अल्प वजन की व्यापकता की सतत पहचान करने के लिए पोषण ट्रैकर का लाभ उठाया जा रहा है।

पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लगभग रीयल टाइम डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। समय पर पाठ्यक्रम सुधार और केंद्रित पहल के लिए केंद्रीय स्तर से लेकर परियोजना स्तर तक विभिन्न स्तरों पर

मासिक डैशबोर्ड और फैक्टशीट प्रदान की जाती हैं।

पोषण केवल खाना खाने तक ही सीमित नहीं है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर (क्रॉस कटिंग) अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**ठिगनापन %**	**अल्प वजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका संबंधित समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों के कद और वजन में वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने, 17% बच्चे अल्प वजन के और 5.2% बच्चे कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की कद और वजन के विकास मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए।

उपरोक्त एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से भारत भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

देश में कुपोषित बच्चों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय क्षेत्र में कुपोषित बच्चों का विवरण **अनुलग्नक-II** पर है।

कुल पंजीकृत बच्चों और मापे गए बच्चों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-III** पर है।

अनुलग्नक-I

"पोषण ट्रैकर कार्यक्रम" के संबंध में श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी और डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 272 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर के अनुसार अक्टूबर 2024 में देश में कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	ठिगनापन %	दुबलापन %	अल्प वजन %
आंध्र प्रदेश	22.6	5.3	10.8
अरुणाचल प्रदेश	32.8	4.2	9.6
असम	42.4	3.8	16.4
बिहार	43.8	9.2	22.9
छत्तीसगढ़	21.5	7	13.1
गोवा	4.1	0.6	1.7
गुजरात	40.8	7.8	21
हरियाणा	28.2	4.1	8.7
हिमाचल प्रदेश	18.4	1.7	6.3
झारखंड	43.8	6.2	19.3
कर्नाटक	39.7	3.2	17.1
केरल	34.4	2.3	9.5
मध्य प्रदेश	46.5	7	26.5
महाराष्ट्र	47.7	4.1	16.5
मणिपुर	7.7	0.3	2.6
मेघालय	18.2	0.4	4.5
मिजोरम	26.7	2.3	5.9
नागालैंड	28	5.3	6.6
ओडिशा	29.1	2.9	12.8
पंजाब	18.4	3	5.9
राजस्थान	36.6	5.5	17.7
सिक्किम	9.2	1.5	1.7
तमिलनाडु	13.4	3.6	7.1
तेलंगाना	32.6	5.6	16.2

राज्य	ठिगनापन %	दुबलापन %	अल्प वजन %
त्रिपुरा	40.5	6.3	16.6
उत्तर प्रदेश	48	3.9	19.4
उत्तराखंड	21	1.5	5.4
पश्चिम बंगाल	38	7.5	13
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.7	2.3	3.9
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	35.9	3.4	16.1
दिल्ली	41.9	3	20.6
जम्मू एवं कश्मीर	12.1	0.7	3
लद्दाख	11	0.2	2
लक्षद्वीप	46.5	11.9	25.1
पुदुचेरी	40.2	6.8	13
संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	26.3	1.8	11.9

अनुलग्नक-II

"पोषण ट्रैकर कार्यक्रम" के संबंध में श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी और डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 272 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर के अनुसार अक्टूबर 2024 में देश में कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

i) जलगांव संसदीय क्षेत्र में बच्चों की पोषण स्थिति इस प्रकार है*:

जिला	ठिगनापन %	दुबलापन %	अल्प वजन %
जलगांव	48.89	3.21	17.20

ii) उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र में बच्चों की पोषण स्थिति इस प्रकार है*:

जिला	ठिगनापन %	दुबलापन %	अल्प वजन %
अमरोहा	52.66	5.17	23.56
हापुड़	50.58	0.80	17.59

* पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 के आंकड़े

अनुलग्नक-III

"पोषण ट्रैकर कार्यक्रम" के संबंध में श्री श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी और डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 272 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कुल पंजीकृत बच्चों (0-6 वर्ष की आयु के) और मापे गए बच्चों (0-6 वर्ष की आयु के) की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

कुल पंजीकृत बच्चे	8,82,87,007
मापे गए कुल बच्चे	8,55,38,380

* पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 के आंकड़े

*****